इकाई 12 जापान में आधुनिकीकरण-III

इकाई की रूपरेखा

- 12.0 उद्देश्य
- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 मेजी पूर्नस्थापना एवं अर्थव्यवस्था
- 12.3 आर्थिक विकास का प्रारंभिक दौर
- 12.4 मूलभूत संरचना का निर्माण
- 12.5 मजदूर संघों का विकास
- 12.6 ग्रामीण क्षेत्र
- 12.7 मूल्यांकन
- 12.8 सारांश
- 12.9 शब्दावली
- 12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद :

- आपको आधुनिक काल से पूर्व की जापान की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं तथा इसके मेजी काल में हुए रूपांतरण का ज्ञान होगा,
- आधुनिक औद्योगिक मूलभूत संरचना के निर्माण के विषय में भी आपको ज्ञान होगा,
- मेजी सरकार की आर्थिक नीतियों का बोध भी आपको होगा,
- आपको श्रमिक संगठनों तथा फैक्टरी कानूनों के विकास का ज्ञान हो सकेगा,
- आप कृषि में हुए विकास को जान सकेंगे, और
- आप आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में राज्य की भूमिका को भी जान जायेंगे।

12.1 प्रस्तावना

मेजी जापान के आर्थिक रूपांतरण ने वहुत अधिक रुचि एवं ध्यान को आकर्षित किया है और इसका कारण यह है कि जापान एशिया के देशों में एक है जो औद्योगीकरण के सबसे सफलता के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इस सफलता के कारण विद्वान लोग इस संदर्भ में मेजी शासकों द्वारा अपनायी गयी नीतियों तथा कार्यक्रमों का विश्लेषण करने की और प्रेरित हुए। इस पर विस्तृत वहस हुई है कि पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण क्या दोनों एक समान हैं। लेकिन जापान के उदाहरण से स्पष्ट है कि एक औद्योगिक समाज के लिये पश्चिमी समाज के समरूप होना आवश्यक नहीं है। इससे पूर्व की इकाईयों से आप इस पक्ष के विषय में पढ़ चुके हैं।

यह प्रश्न कि जापान की आधुनिक अर्थव्यवस्था से पूर्व की अर्थव्यवस्था ने जापान के आधुनिक विकास के लिये कैसे योगदान दिया स्वयं में एक जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न पर आर्थिक इतिहासकारों के विचार एक समान नहीं है। लेकिन उनमें से अधिकतर यह स्वीकार करते हैं कि आर्थिक संस्थाओं एवं परम्पराओं के व्यापकतर विकास के कारण ही शानदार तीव्रता एबं शीव्रता के साथ आधुनिक आर्थिक संगठन का निर्माण संभव हो सका।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ने भी योगदान किया। यद्यपि पश्चिमी साम्राज्यवादी दबाव ने एक संकट की भावना को उत्पन्न किया किन्तु जापान को जो समय प्राप्त हुआ उसका उसने शीघ्रता एवं प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये प्रयोग किया। प्रौद्योगिकी की प्रचुरता तथा कौशलता को प्रतिबंधित नहीं किया गया और इस तरह से जापान अपने नेताओं को देश के वाहर उचित कौशल एवं साधनों के लिये भेज सका।

जापान : अधुनिकीकरण की ओर संक्रमण

अंत में यह भी स्मरण रखा जाना चाहिये कि जापान अपने संसाधनों में काफी कमजोर है, लेकिन उसके पास पर्याप्त कोयले के भण्डार थे और उन्नीसवीं सदी में औद्योगिकीकरण का आधार कोयला ही था।

इस इकाई में मेजी पुर्नस्थापना के समय की आर्थिक स्थिति का विवेचन किया गया है और मेजी शासकों की नीतियों की व्याख्या भी की गयी है। इस इकाई में कृषि सुधारों के साथ-साथ औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में राज्य के द्वारा किये गये प्रयासों का भी विवेचन किया गया है। बैंकों की संस्थाओं तथा विदेशी व्यापार के योगदान का भी विवेचन किया गया है। तेजी के साथ हुए औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप मजदूर संघों के अंतर्गत मजदूर आंदोलन का भी उद्भव हुआ। इस इकाई में इस संदर्भ में सरकार की नीतियों का विवेचन किया गया है।

12.2 मेजी पुर्नस्थापना एवं अर्थव्यवस्था

नयी मेजी सरकार को तोकुगावा बकुफु से उत्तराधिकार में कई तत्कालिक समस्यायें प्राप्त हुई थीं और इन समस्याओं में सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण समस्या एकित्रत हुए कर्ज की थी। बकुफु की वित्तीय समस्या तथा हान के बढ़ते कर्ज ने तोकुगावा के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस विशाल कर्ज के प्रबंध के साथ-साथ वह कर्ज जो पुर्नस्थापना के युद्धों के कारणवश हुआ इस समय गंभीर समस्या बना हुआ था और नये शासकों को इसका सामना करना पड़ा। कृषि ही इस समय एक मात्र राजस्व का स्थायी स्रोत था और इसी कारणवश सरकार ने कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि के कर्ज को कम करने के लिये सैमुराई के करों में कटौती की गई। तोकुगावा शासन के दौरान सैमुराई परिचर राजस्व के 30 प्रतिशत को निजी भत्तों के रूप में प्राप्त करते थे। हान के अंतर्गत दाइम्यो को इदो में बनाये रखने पर खर्च करते थे। इस 20 प्रतिशत की मांग उनके द्वारा इसलिये की जाती क्योंकि इदो में कभी-कभी उपस्थिति देने की प्रथा थी। सरकार ने इन निजी भत्तों को कम करने तथा भूमिकर को सुधारने के लिये तुरंत कदम उठाये। इन निजी भत्तों को सरकारी ऋण पत्रों में या एकमुश्त अदायगी में रूपांतरित कर दिया गया। इस राशि को प्रभावशाली तरीके से और कम किया गया और ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि मुद्रा स्फीति में लगातार वृद्धि हो रही थी। इस तरह से सरकार वित्तीय उत्तरदायित्वों का प्रबंध करने में सफल हो पायी। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इन आर्थिक सुधारों के कारण हथियारबंद विद्रोह फूट पड़े और परंपरागत विशिष्ट वर्ज के बीच भी असंतोंष बढ़ा।

कृषि सुधार अगला निर्णायक क्षेत्र था। यद्यपि कृषि में सुधारों के कार्य का प्रारंभ 1873 में हुआ किन्तु इसको पूर्ण होने में छः वर्ष का समय लगा। तोकुगावा के समय में भूमि कर उत्पादन पर आधारित था और सैद्धांतिक तौर पर उसकी अदायगी चावल के रूप में की जाती थी। लेकिन सुधारों के साथ कर को भूमि के अनुमानित किये गये मूल्यों के आधार पर नकद अदा किया जाने लगा। राष्ट्रीय कर की दर अनुमानित किये गये भू मूल्य पर 3 प्रतिशत तथा स्थानीय कर राष्ट्रीय कर का एक तिहाई भाग था। अब कर देने वाले भूमि के स्वामी बन गये।

इन उपायों को कुछ ऐसे परिवर्तनों के द्वारा पूर्ण किया गया जैसे कि भूमि के उपयोग पर लगे प्रथागत प्रतिबंशों तथा भूमि सर्वेक्षणों को समाप्त करके पूरा किया गया। सरकार ने यह प्रयास किया कि विद्रोह आदि न हो, लेकिन इसके बावजूद भी विरोध आंदोलन हुए और इन सबमें महत्वपूर्ण वाकायाम मण्डल में घटित 1876 का विद्रोह था। यद्यपि सरकार ने प्रारंभिक स्थिति में कड़ा रुख अपनाया लेकिन दूसरे सैमुराई विद्रोहों के कारण इसके रवैये में कुछ लचीलापन आया और भूमि कर को बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत तक कम कर दिया गया। इस कमी का तात्पर्य वार्षिक कर में 17 प्रतिशत की कमी होना था।

1874-1881 के बीच के वर्षों में यह राजनीतिक तौर पर एक सफल उपाय था क्योंकि इन वर्षों में विरोध करने की मात्र 99 घटनाएं हुई और इनमें 37 घटनायें ज़मींदारों एवं काश्तकारों के बीच के झगड़े थे। अब कर निर्धारण को समान तथा तर्क संगत बना दिया गया। लेकिन इस प्रणाली से भी ज़मीदारों को ही अधिक लाभ हुआ और ऐसा विशेष रूप से वहां पर हुआ जहां परम्परागत भूमि अधिकारों को स्थायी तौर पर काश्तकारों को हस्तांतरित नहीं किया गया। इसके कारण जमींदारों एवं काश्तकारों के बीच झगड़ों में भी वृद्धि हुई। लेकिन सिदनेय क्राकौर के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कर का नया दर उत्पादन के भाग के रूप में पुराने कर से अधिक न था और कूछ मामलों में वह वास्तव में कम था।

''भूमि कर का मुख्य प्रभाव यह हुआ कि अब भूमि ऐसी पूंजी सन्पदा हो गई जिसको बाजार में बेचा एवं खरीदा जा सकता था।''

12.3 आर्थिक विकास का प्रारंभिक दौर

1868 से 1885 के बीच के वर्ष ऐसा समय था जबिक सरकार ने आर्थिक विकास के लिये एक व्यवस्था को कायम करने तथा मूलभूत कार्य की नींव रखने का प्रयास किया। भेजी सरकार को उत्तराधिकार में न केवल विशाल कर्ज प्राप्त हुआ था बल्कि कुछ नयी निर्मित फैक्टिरियां एवं जहाज बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए। भेजी नेताओं की राजनीतिक आवश्यकताओं ने उनको रक्षा उद्योगों को विकसित करने के लिये बाध्य किया जबिक वे अपने राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित कर ही रहे थे। तोकुगाबा के अंतिम वर्षों में बकुफु के साथ-साथ बहुत से हानों ने भी अपने लोहे के कल-कारखानों को मोटे-तौर पर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। उदाहरण के लिये, हिजैन के हान ने 1850 में लोहा पिघलाने की एक बड़ी भट्टी की स्थापना की थी और इसके फलस्वरूप यह अपने द्वारा उत्पादित लोहे से तोप बनाने में सफल हो सका।

इसी तरह से जहाज निर्माण के क्षेत्र में भी कुछ प्रगित हो चुकी थी। बकुफु तथा कुछ हानों ने भाप से चालित जहाजों का निर्माण कर लिया था। कोयला खानों का आधुनिकीकरण किया गया और सूत कातने वाले कारखानों का भी निर्माण हुआ। मेजी सरकार ने इस थोड़े विकसित आधार को निर्मित करके विकास की आधारिशला को तैयार किया। सरकार को विदेशी व्यापार से होने वाली आमदनी में भी कमी का सामना करना पड़ा। इसलिये इस सरकार ने उस मूलभूत संरचनात्मक आधार का निर्माण किया जिससे जापानी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। नेतागण इसके लिये भी सतर्क थे कि कहीं जापान विदेशी सामान के लालच में न फंस जाये। पूंजी खर्च के लिये व्यवसायकर्त्ताओं को स्वयं ही भारी प्रयास करने होते थे और इसलिये सरकार इस आशा के साथ आयात एवं कारखानों को स्थापित कर रही थी कि इससे नयी प्रौद्योगिकी तथा संगठनात्मक तौर-तरीके लागू होंगे।

उदाहरण के तौर पर, 1872 में तोमिओका में रेशम को कीड़ों से उत्पन्न करने वाले कारखाने को स्थापित किया गया। सरकार के ये अधिकतर कारखाने ठीक प्रकार से कार्य न कर सके लेकिन इसी के साथ-साथ उन्होंने प्रयोगशालाओं का कार्य किया और कृषि को सबसे नयी प्रौद्योगिकी तथा उपायों के संपर्क में लाया जा सका। सरकार ने इस तरह के व्यवसायों पर 1868-1881 के वर्षों में लगभग 3 करोड़ 64 लाख येन खर्च किये। इन कारखानों ने निजी कारखानों को कम मूल्य पर माल उपलब्ध कराया और इस तरह से व्यवसायी लोग पूंजीवाद के विकास की आधारशिला को सफलतापूर्वक रख सके।

कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को लेकर वाद-विवाद बना हुआ है यद्यपि यह क्षेत्र वृद्धि एवं विकास के लिये निरंतर राजस्व को उपलब्ध कराता रहा। काजूशी ओखावा ने अनुमान लगाया है कि 1878-1882 के बीच के वर्षों में कृषि उत्पादन का वार्षिक मूल्य वर्तमान दामों में 43 करोड़ 20 लाख येन था।

1874 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्पादन का 60 प्रतिशत कृषि से, 30 प्रतिशत औद्योगिक सामानों से तथा शेष खान, मछली पालन एवं जंगलों जैसे उद्योगों से प्राप्त होता था। कृषि के क्षेत्र में चावल मुख्य फसल थी। यह बड़ा ही रुचिकर है कि चावल से तैयार होने वाली शराब सेक तथा अन्य तैयार की गयी भोजन सामग्री औद्योगिक उत्पादन का 42 प्रतिशत थी और शेष धागा एवं कपड़ा था।

इस सर्वेक्षण से पुर्नस्थापना के समय की अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताओं का ज्ञान होता है और इससे यह भी स्पष्ट है कि पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में यह अभी भी अविकसित अर्थव्यवस्था थी।

1881 में मत्सुकाता मसायोगी वित्त मंत्री बना और उसको उस मुद्रा-स्फीति का हल ढूंढना था जिसका सामना जापान को करना पड़ रहा था। इसका कारण यह था कि जहां एक और आमदिनयों में कमी हो रही थी वहीं दूसरी और सोना-चांदी का निकास भी हो रहा था। मत्सुकाता ने सोना-चांदी में वृद्धि करते हुए मुद्रा के संचरण में कमी की। इसका प्रभाव यह हुआ कि इसने व्यवसायिक लोगों की स्थिति को और मजबूत किया और संसाधनों को आधुनिक क्षेत्र की ओर अग्रसर कर दिया। अर्थव्यवस्था में मंदी ने समाज के कमजोर लोगों को बहुत गहराई से प्रभावित किया और काश्तकारों तथा छोटे किसानों की हालत और खराब हो गई।

रूपान्तरण तथा हान के कर्जों को समाप्त करने (यह कर्ज अनुमानतः 4 करोड़ 70 लाख येन का था) जैसे उपायों ने सरकार तथा ग्रामीण धनी लोगों के हाथों में निवेश करने के लिये संसाधनों को हस्तांतरित करने में मदद की। इसने अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए मूल ढांचे को सुनिश्चित कर दिया। यहां पर जिस बात पर बल दिया गया है वह यह है कि तोकुगावा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निश्चय ही कुछ ऐसी संस्थायें थी जिनके कारण मेजी शासकों के लिए आधुनिक अर्थव्यवस्था को निर्मित करना संभव हो सका। लेकिन जामेज नाकामूश जैसे विद्वानों का कथन है कि इस समय विकास दर कोई विशेष अधिक न थी। इस तरह के

जापान : आधुनिकीकरण की ओर संक्रमण कथनों का सुझाव है कि मेजी शासक अधिक सफल इसलिए हो सके क्योंकि वे खपत को सीमित कर सके और द्वितीय विश्व युद्ध तक इसको कम बनाये रखा गया।

12.4 मूलभूत संरचना का निर्माण

अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि का मुख्य कारण मूलभूत संरचना के निर्माण में सरकार के द्वारा किया गया विशाल खर्च था। 1872 में संयुक्त राज्य अमेरीका के आधार पर राष्ट्रीय बैंक अधिनियम बनाया गया और इसके कारणवश 150 राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना हुई। कुछ निजी बैंक भी थे और प्रारंभ में पूंजी का स्रोत रूपांतरण था। ई.एच. नौरमैन के अनुसार, ''सामंतीय जमींदार अब क्षेत्रीय जमींदार न रह गये थे और न वे किसानों से अपनी आमदनी को प्राप्त करते थे, बल्कि वे अब रूपांतरण के बल पर वित्तीय रईस बन गये थे। वे नई पूंजी को बैंकों, स्टॉकों, उद्योगों या भू-सम्पत्तियों में निवेश कर रहे थे और इसलिये वे छोटे वित्तीय अल्पतंत्रों में शामिल हो गये।'' धीरे-धीरे ग्रामीण धनी एवं व्यवसायी लोगों का इस क्षेत्र में प्रभुत्व कायम हो गया। 1900 तक हाइपोथिक बैंक, औद्योगिक बैंक आदि इस तरह के कई बैंक थे। मेजी सरकार की सलाह पर बड़े वित्तीय घरानों ने भी त्सूशो कैश (वाणिज्यिक कम्पनियां) एवं क्वाजे कैश (विनिमय कम्पनियां) का गठन किया। इन कैशों को त्सूशोशि (वाणिज्यिक ब्यूरो जिसकी स्थापना 1869 में की गई थी) के द्वारा संचालित किया जाता था। बैंकिंग तथा ऋण पूंजी की आपूर्ति काफी हद तक राज्य द्वारा की जाती थी। मेजी सरकार ने इस अवसर का उपयोग ऐसे उद्योगों को विकसित करने के लिये किया जिनमें विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता थी। यहां पर यह उद्धृत करना उचित होगा कि पूंजी संचयन ने औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 19वीं सदी के अंत तक ऋणों पर ब्याज दर 12 से 18 प्रतिशत तक थी जबिक जमा पूंजी पर यह दर 7 से 8 प्रतिशत थी।

परिवहन एवं संचार को भी बहुत महत्व दिया गया। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण टोकियो से योकोहामा तक किया गया और 1881 तक जापान में मात्र दो सौ मील लम्बी रेलवे लाईन थी। इस क्षेत्र में सरकार ने निजी निवेशकर्ताओं को उनके द्वारा निवेश की गई राशि पर गारंटी देकर प्रोत्साहित किया। उदाहरण के तौर पर, जापान में 1903 तक कार्य करने योग्य रेलवे लाईन की लम्बाई 4,500 मील थी और इस रेलवे लाईन का 70 प्रतिशत निर्माण निजी कम्पनियों के द्वारा किया गया था। 1906 में रेलवे राष्ट्रीयकरण अधिनियम के द्वारा 17 कम्पनियों का अधिग्रहण कर लिया गया और शाही रेलवे कम्पनी को अदा की गई राशि अन्य सभी औद्योगिक कम्पनियों को अदा की गई कुल राशि से कहीं अधिक थी।

सरकार ने जहाज निर्माण के क्षेत्र में देशी व्यवसायिक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिये चुनिन्दा छूटों की नीति का अनुसरण किया। प्रारंभ में इवास्की यातारो की मित्सुबिशी कम्पनी को विशाल छूट प्रदान की गई और इसने प्रभावशाली ढंग से विदेशी प्रतिद्वंद्विता का सामना किया। लेकिन शीघ्र ही इस स्थिति में परिवर्तन हो गया और 1885 में एन.वाई.के. (निपोन युजेन कैश) की स्थापना की गई और शीघ्र ही यह एक बड़ी कम्पनी बन गई। 1883 से 1913 तक सरकार ने इस कम्पनी को विशेष छूटें प्रदान की जिससे कम्पनी अपने जहाज़ी बेड़े का विस्तार कर सकी और जापानी बंदरगाहों तक उनके जहाज 50 प्रतिशत टन भार पहुंचाने लगे। जहाज निर्माण उद्योगों के विकसित होने के फलस्वरूप इंजीनियरिंग तथा दूसरे संबंधित कारीगरी के कार्यों का विकास भी हुआ।

ठीक इसी तरह से विद्युत शक्ति के उत्पादन में वृद्धि हुई और जल विद्युत निर्माण तथा उच्च तनाव को परिवर्तित करने के क्षेत्र में तकनीकी विकासों के कारण विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई। सस्ते श्रम तथा सस्ते पूंजी मूल्यों के कारणवश छोटी कम्पनियों ने सस्ते विद्युत मोटरों को खरीदा और इसकी वजह से उनके उत्पादन में वृद्धि हुई।

जापान का आर्थिक परिदृश्य रूपांतिरत होने लगा। आर्थिक इतिहासकार नाकामूरा तक फूसा प्रारंभिक काल का विवरण देते हुए कहते हैं कि आधुनिक उद्योग परम्परागत उद्योग के अथाह समुद्र में दूर-दूर बसे द्वीपों की भांति होता है। लेकिन एक बार इन नये विंकास को लागू कर देने के फलस्वरूप धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। 1883-1913 के मध्य श्रम शक्ति 2 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख हो गई। रोजगार अभी भी परम्परागत क्षेत्र में ही अधिक था और इसके अंतर्गत 60 प्रतिशत मजदूर कार्यरत थे। कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत तथा दूसरे 40 प्रतिशत के लिये अन्य दूसरे क्षेत्र थे।

कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक क्षेत्र का विकास अभी भी मध्यम गति से हो रहा था और परम्परागत क्षेत्र ने ही जापान की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी खेतों के आकार में कम ही परिवर्तन हुआ था। एक कृषि अधीन औसतन एक हैक्टर भूमि होती थी और इस काल में यही स्थिति बनी रही। फिर भी भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा और 1885 से 1914 तक काश्तकारी 35 से 45 प्रतिशत तक बढ़ी। जमींदारों की संख्या तथा शक्ति में वृद्धि व्यापार एवं राजनीति में उनकी बढ़ती भूमिका के द्वारा स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है।

कृषि विकास एक और अन्य वाद—विवाद का विषय है। लेकिन यहां पर एक संकेत यह मिलता है कि उत्पादन का सकल कृषि मूल्य 17 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से 1934-36 की स्थिर कीमतों के आधार पर बढ़ा। यह विकास रसायनिक खादों, मशीनों तथा श्रम शक्ति में वृद्धि तथा तकनीकी परिवर्तनों के कारण हुआ। ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास ने भी नये विचारों को फैलाने के साथ-साथ बाजार प्रणाली को सुधारने में योगदान दिया। यहां पर यह भी जानना आवश्यक है कि जापान की कृषि को यूरोपीय तकनीक के आयात करने के प्रयास से कोई लाभ नहीं हुआ। ये प्रयास असफल रहे लेकिन जापान में परम्परागत छोटे स्तर पर कृषि का ही चलन रहा और इसमें सुधार लाए गए इससे जापान की कृषि व्यवस्था को लाभ पहुंचा।

कृषि में विकास की दर कुछ भी रही हो, चाहे वह उतनी उच्च रही हो जैसा एक समय समझा जाता था किन्तु ध्यान देने, योग्य बात यह है कि मांग के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता रहा और कभी भी इसकी कमी नहीं रही। 1880 में कृषि में 1 करोड़ 70 लाख श्रमिक थे और उस समय जापान की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 60 लाख थी। किन्तु 1920 तक कृषि में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में गिरावट आयी और वह 1 करोड़ 40 लाख रह गई। परन्तु इस समय तक कुल जनसंख्या 5 करोड़ 50 लाख तक बढ़ गई। उपनिवेशों से खाद्य पदार्थों का आयात नहीं किया जाता था और जो कुछ होता भी था, वह नगण्य था। अन्य विकासशील देशों से भिन्न, जापान में आमदनी में बढ़ोत्तरी होने पर भी खाने की आदतों में परिवर्तन नहीं हुआ। आमदनी की असमानता होने के कारण धनी लोग धन बचत करने में योगदान करते थे और गरीबों के बीच खपत में कमी आती।

विदेशी व्यापार ने भी उस समय प्रारंभिक तौर में निर्णायक भूमिका अदा की जबिक वह कुल व्यापार का 6 प्रतिशत था, लेकिन 1905 में वह 28 प्रतिशत हो गया। प्रारंभ में रेशम निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी, लेकिन धीरे-धीरे निर्यात में कृषि पदार्थों में कमी होने लगी। यद्यपि अभी भी वे कुल उपभोग वस्तुओं के निर्यात में एक चौथाई का योगदान कर रहे थे।

परम्परागत उद्योग ने माल की आपूर्ति के साथ-साथ पूंजी निर्माण तथा निर्यात में भी योगदान दिया। प्रारंभ में भेजी सरकार ने व्यापार संगठनों को संगठित करने का प्रयास किया और बाद में इस सरकार ने उन उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान दिया जो नयी तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन 1879 में उस समय से जबिक ओसाका चेम्बर ऑफ कामर्स ने परम्परागत व्यापार को संगठित करने के प्रयास किये, इस क्षेत्र को संगठित करने के लिये बहुत से कानूनों को बनाया गया। वास्तविकता यह है कि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की मांगों की आपूर्ति करता था और सस्ती विद्युत एवं परिवहन को प्राप्त करने के साथ-साथ यह क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र में उत्पादित सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की चीजों के समक्ष ही उत्पादन करता था। अन्त में, परम्परागत तौर पर उत्पादित किये गये उत्पादन निर्यात बाजार में भी सफलता पूर्वक प्रतियोगिता करते थे। इसिलये सिदनेय क्राकौर यह तर्क प्रस्तुत करता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जापान में औद्योगिक विकास वास्तव में परम्परागत क्षेत्र का ही विकास-था।

कुछ मायनों में जापान का अनुभव पश्चिमी देशों से भिन्न प्रकार का था। पश्चिमी देशों में औद्योगिकीकरण सामान्य तौर पर छोटे उद्योगों जैसे कि कपड़ा, खान एवं धातुकर्म रसायनों से प्रगति करता हुआ विशाल उत्पादन माल के रूप में हुआ। लेकिन जापान में स्थिति इससे कुछ भिन्न थी और जापानी रेलवे का विकास, लौह तथा स्टील उद्योग से पूर्व ही हो गया क्योंकि आवश्यक सामग्री एवं कल पुर्जों का आयात किया गया। कपड़ा उद्योग की स्थापना ठीक उसी समय हुई जिस समय लौह एवं स्टील, जहाज निर्माण आदि का निर्माण प्रारंभ हुआ। दूसरे शब्दों में इन उद्योगों की स्थापना इस कारण से हो पाई कि राज्य ने स्वयं विशेष छूटों एवं संरक्षण के माध्यम से इनके उत्तरदायित्व को वहन करने की इच्छा रखी। आर्थिक सहायता देने का आधार राष्ट्रीय हित होते थे न कि योजना से होने वाला आर्थिक लाभ।

1896 ई. में जहाज निर्माण प्रोत्साहन अधिनियम इसका जीवांत उदाहरण है कि राज्य किस तरह राष्ट्र-निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहता था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि अगर स्टील भाप जहाज का निर्माण पूर्ण रूपेण से अपने ही कारखाने में किया जाता है तब 700-1000 टन के जहाज पर छूट 12 येन प्रति टन के हिसाब से दी जायेगी और 1000 टन या इससे अधिक के जहाज पर छूट 20 येन प्रति टन होगी। यदि

जापान : आधुनिकीकरण की ओर संक्रमण जहाज के इंजन का निर्माण जापानियों ने किया है तब प्रति अश्वशक्ति पर 75 येन अतिरिक्त सहायता के तौर पर दिया जायेगा। विदेशों में निर्मित जहाजों के साथ प्रतियोगिता करने में यह पर्याप्त न था और इसी कारण समुद्र परिवहन छूट अधिनियम में 1899 में संशोधन किया गया तथा इस अधिनियम के द्वारा विदेशी निर्मित जहाजों की छूट को घरेलू निर्मित जहाजों के मुकाबले में कम करके आधा कर दिया गया और इससे घरेलू व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हुई।

अगर आधुनिक क्षेत्र के विकास का अध्ययन किया जाये तब हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि इसका घनिष्ठ संबंध सैनिक मांगों से था। जब कभी सैनिक खर्च में बढ़ोत्तरी होती तब आधुनिक क्षेत्र में वृद्धि होती और ऐसा चीन-जापान एवं रूस-जापान युद्धों के समय हुआ। डब्लू.डब्लू. लौकवूड जैसे विद्वानों ने इसे धन की निकासी का नाम दिया लेकिन कोजो यामामूरा जैसे विद्वानों ने तर्क दिया कि इसने पश्चिमी तकनीकी एवं कौशलता को जापान में फैलाने में मदद की।

नापान की अर्थव	यवस्था पर	भ-कर व	हे प्रभात	में की ति	वेचना की	जिये। त्य	तर लगा	ग्र 10	पंक्तियों व
तानान प्रा जापण	वयरवा यर	नू पार प	יודיא מי	ना प्रगाप	નવના વગા	1919 1 5	(16 (0))	10	भाषताचा *
									1 5
100									
ापान के प्रमुख	क्षेत्रों में और	होगिकी	करण व	लिए सर	कार ने ज	ते प्रयास	किये उ	नकी वि	वेचना की
त्तर लगभग 10			नारण प	1000	,पगर ग ०	॥ त्रपारा	1979 0	1971 19	प्रवचा प्रा
त्तर लगमग 10	पक्तियों में	द।							
त्तर लगमग 10	पक्तियों म	द।		- 5 P	4. 16. 2				
त्तर छगमग 10	पक्तियां म	द।	÷ 1	10 P	1. 15. 7				ere di anni
त्तर छगमग 10	पक्तियां म	द। 						7 (A)	The s
त्तर ७गमग 10	पक्तिया म	۲۱ 		100				X	The contract of the contract o
त्तर ७गमग 10								7 (A)	Section 1
त्तर ७गमग 10									Ann -
त्तर ७गमग 10									
त्तर ७गमग 10									500 - 1
त्तर ७गमग 10									
त्तर ७गमग 10									Sec.
त्तर ७गमग 10									
त्तर ७गमग 10									
त्तर छगमग 10									Grand Control of the
त्तर ७गमग 10									
									6 p. 10
या जापान के उ									6 p. 10
या जापान के उ				पश्चिमी	देशों के	अनुभव			6 p. 10
				पश्चिमी		अनुभव			6 p. 10
या जापान के उ		 тण का	अनुभव	पश्चिमी	देशों के	अनुभव	के समान	था?	उत्तर 10

-	3	
जापान	म	आधुनिकीकरण-!!

	165 m m m m m m m

12.5 मजदूर संघों का विकास

प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1890 के आस पास सान फ्रांसिस्को में तकानो फूसातारो के द्वारा की गई थी और जब वह वापस जापान लौटा तब उसने 1897 में एक अन्य श्रमिक संघ की स्थापना की। तकानो सेमुल गोम्पर्स के विचारों से प्रभावित था और उसने सभी उग्रवादी मांगों को मानने से इंकार कर दिया और उसने समाजवाद का भी विरोध किया। तकानो का कहना था धन में असमानता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका अन्त मात्र उदार एवं धीरे-धीरे सुधारों के द्वारा ही संभव है।

मजदूर संघ एवं समाजवादी आंदोलन में दूसरा महत्वपूर्ण नेता कतयामा सेन था। कतयामा सेन ने अपने जीवन का प्रारंभ एक ईसाई समाजवादी के रूप में किया और उसने गरीबों के बीच कार्य किया तथा उसने अपने इस अनुभव के कारण टोकियों में मजदूरों को संगठित किया। 1897 में उसने मजदूर संघों के प्रोत्साहन के लिये एक संस्था की स्थापना की।

ओई केन्तारो नाम का एक उग्रवादी विचारक ओसाका क्षेत्र में सिक्रिय था। उसने व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, रात्रि स्कूलों तथा विशेष बैंकों तक की स्थापना की। उस समय जापान में यह महसूस किया जा रहा था कि श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिये कुछ सुनिश्चित कदमों को उठाया जाना चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये न केवल उनको संगठित करना पर्याप्त था बल्कि उनकी शिक्षा तथा भौतिक तौर पर अच्छे जीवन के लिये सुविधाओं को जुटाने की भी आवश्यकता थी।

प्रारंभिक मजदूर आंदोलन के नेता अपने विचारों एवं कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर उदार थे और वे सौहार्दता एवं सहयोग के साथ कार्य करने पर बल देते थे। लेकिन कतयामा का कहना था कि ऐसे सामन्तीय संबंध जो श्रिमेकों तथा पूंजीपितयों के बीच के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, उनका निश्चय ही अन्त होना चाहिये। उनकी उदारता के बावजूद सरकार ने उनके आंदोलन का तीन वर्षों के अंदर ही दमन कर दिया और इस कार्यवाही के कारण ये नेतागण यह सोचने के लिये बाध्य हुए कि उनको राजनीतिक तौर पर कार्यवाही करनी चाहिये।

समाजवादी आंदोलन बुद्धिजीवियों के बीच शक्ति एवं प्रभाव प्राप्त कर रहा था। 1901 में एक समाजवादी दल का गठन किया गया और इसको भी तुरन्त प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसा कि पहले ही उद्धृत किया जा चुका है कि 1900 के शांति बनाये रखने के कानून के साथ-साथ दूसरे प्रशासनिक एवं नागरिक नियमों, जैसे सरकार के दमनात्मक विधानों का प्रयोग मजदूर संगठनों के विकास को कुचलने के लिये किया गया। सरकार की नीति के कारण श्रमिक आंदोलन कुछ समय के लिये कमजोर पड़ गया लेकिन इसी के साथ-साथ उनके उग्रवाद में इसने बढ़ोत्तरी की और बहुत से श्रमिक नेता वर्ग संघर्ष की वकालत करने लगे।

1904-5 का रूस-जापान युद्ध जापान के आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण विभाजन रेखा है। ठीक इसी समय से लैंह एवं स्टील, कोयला, धातु खनन्, आदि क्षेत्रों का विकास शुरू हुआ और जापान ने भी विदेशों में अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण अधिक ताकत के साथ किया। आर्थिक विकास ने जहां एक ओर उद्योग के क्षेत्र में झगड़ों में वृद्धि की वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान विद्रोहों में भी वृद्धि हुई।

1900 से 1910 के वर्षों में मजदूर आंदोलन का और अधिक ताकत से दमन किया गया और ऐसा बहुत से दमनात्मक कानूनों के अस्तित्व में होने के कारण हो सका। इस दमन की बदौलत ही उस हिंसा में वृद्धि हुई जिसकी अंतिम परिणति 1910 में एशिओ ताम्र खान की घटना के रूप में हुई। ये खानें निक्को के पास ही

जापान : आधुनिकीकरण की ओर संक्रमण स्थित थी और निक्को वातारसे नदी के मुख्यालय पर स्थित है। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु थी और खानों को, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की ओर कोई ध्यान दिए बिना ही व्यापक तौर पर विकसित किया गया। लेकिन जंगलों के काटे जाने के कारण नंदी के पानी संग्रहण क्षेत्र में बाढ़ ने 1896 में भयंकर तबाही की ओर हजारों घर बर्बाद हो गये। इसी के कारण इन खानों का विरोध किया गया और इस तरह से खान, मेजी औद्योगिक विकास के नकारात्मक स्वरूप का प्रतीक हो गई। फरवरी 1909 में एशिओ खान के लगभग 1200 श्रमिक बेहतर कार्य करने की शर्तों तथा बेहतर मजदूरी के लिये हड़ताल पर चले गये।

मेजी सरकार ने दोहरी नीति का अनुसरण किया। जहां एक ओर निर्दयी होकर दमन किया गया वहीं पर दूसरी ओर श्रमिकों के कार्य करने की शर्तों को बेहतर करने के प्रयास भी किये गये जिससे कि सामाजिक अव्यवस्था को कम किया जा सके। सरकार ने तुरंत, समाजवादी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि कीड़ों का अध्ययन करने से संबंधित एक सोसाइटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि इसमें आशंकायुक्त शब्द सोसाइटी (शाकाय) विद्यमान था और जिसका तात्पर्य समाजवाद समझा जाता था।

नौकरशाही ने काम करने की परिस्थितियों का विश्लेषण जल्दी से जल्दी 1882 में शुरू किया और उस समय मात्र पचास फैक्ट्रियां विद्यामान थीं। फैक्ट्री के अंदर जिस आवश्यक कम से कम स्तर को बनाये रखा जाये उसकी रिपोर्ट एवं अध्ययन से स्पष्ट था कि उनको भी कानून में रूपांतरित नहीं किया गया था। प्रथम फैक्ट्री कानून को व्यापारिक घरानों के विरोध के बावजूद 1911 में पारित किया गया लेकिन इस कानून में खामियों को छोड़ दिया गया और उद्योग को इसको अपरिहार्य तौर पर लागू करने से पूर्व काफी समय मिल गया।

12.6 ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले रूपांतरण में अधिक रुचि ली गई। मेजी भू-बन्दोबस्त में उन परम्परागत परिपाटियों तथा रीतियों को हटा दिया जिसने समय पर किसान को संरक्षण प्रदान किया था और अब वे जमींदारों के दबावों में और अधिक आ सकते थे। पट्टेधारी अधिकारों को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता था और जमींदारों के सम्पत्ति अधिकारों पर कोई सीमा न थी। यही वह कारण था जिससे प्रारंभिक वर्षों में पट्टेधारी के अधिकारों को लेकर झगड़ों में वृद्धि हुई। यद्यपि भूमि कर को 3 प्रतिशत से कम करके 2.5 प्रतिशत कर दिया गया था, लेकिन काश्तकारों के वित्तीय उत्तरदायित्वों में कोई कमी न आयी थी।

1870-1880 के वर्षों में बहुत से काश्तकारी झगड़े अनिभज्ञता के कारण सामने आये क्योंिक पुर्नस्थापना के समय काश्तकारों के विभिन्न स्तर विद्यमान थे और उनका धीरे-धीरे प्रचलन समाप्त हो गया। अधिकतर काश्तकारों ने अनेकों जमींदारों से भूमि को किराये पर प्राप्त किया था तािक वे अपने जोखिम को कम कर सकें। भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। इसी कारण से जमींदारों ने रेशम के धागे के उत्पादन जैसे ग्रामीण उद्योगों को अपना लिया। वे महाजनी का कार्य भी करते थे। ऐन वासवो का तर्क है कि जमींदार ग्रामीण समाज में अभिजात थे और 1900 तक उन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

सरकार ने जमींदारों को अपनी भूमि को सुसंगठित करने के लिये सिक्रिय समर्थन दिया और ऐसा इसलिये किया गया जिससे कि सिंचाई तथा जल-निकास की बेहतर सुविधाओं को मुहैया कराया जा सके। काश्तकार लोग शहरों में बेहतर जीवन स्तर की ओर आकर्षित हुए क्योंकि वहां पर मजदूरी अधिक थी और इसके कारण कृषि में श्रमिकों की कमी हो गई। किन्तु जमींदारों के लिये स्वयं खेती करने की अपेक्षा भूमि को पट्टेदारों को देना ही अधिक लाभदायक था। सरकार के लगातार बढ़ते खर्च के कारण अब सार्वजनिक कार्यों एवं शिक्षा का उत्तर दायित्व स्थानीय सरकारों का हो गया। स्थानीय सरकारों को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त कर लगाना पड़ा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव का एक अन्य स्रोत पैदा हो गया।

ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को कम करने के लिये सरकारी नौकरशाही ने ग्रामीण सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया। यह उस कार्य की ही एक निरंतर कड़ी थी जिसको 1870 के वर्षों में होतोकुशा या रिपेईग वरच्यू सोसाइटी ने किया था। इन सौसाइटियों का गठन जमींदारों के अधीन किया गया और ये 18वीं सदी के कृषि सुधारक निनोमिया सौन्तोकू के उचित उपदेशों पर आधारित थीं। उन्होंने जहां एक ओर उचित सदाचार को विकसित करने के प्रयास किये वहीं पर उन्होंने कृषि में भी व्यवहारिक सुधारों को करने का

जापान में आधुनिकीकरण-III

प्रयास किया। नौकरशाही में इस तरह के दृष्टिकोण के कारण अनेक कानून पारित किए गए जैसे औद्योगिक सहकारी अधिनियम 1899 को लागू कर दिये जाने पर साख, उपभोक्ता बाजार तथा उत्पादकों की सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहना प्राप्त हुआ। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायित्व की परिस्थितियों को लागू करना था क्योंकि जहां एक ओर यह राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये अति महत्वपूर्ण था वहीं पर सामाजिक स्थायित्व के लिये भी। वे राष्ट्रीय वफादारी एवं देश शक्ति को प्रोत्साहित करने वाले रास्तों की तलाश कर रहे थे।

1908 में शाही आज्ञा पत्र (बोशिन शोशो) के द्वारा जापानी जनता से कड़ी मेहनत तथा सहयोग की अपील की गई जिससे कि उनके प्रयासों के द्वारा ''हमारे साम्राज्य की बढ़ती सम्पन्नता को सुनिश्चित किया जा सके।'' सरकार ने सामूहिक प्रयासों के इन विचारों के प्रसार के लिये युवक संगठनों एवं सैनिक ऐसोसिएशनों का उपयोग किया। यह सामूहिक प्रयास ''समाज की सुरक्षा को संरक्षण'' प्रदान करेगा।

12.7 मूल्यांकन

मेजी सरकार ने औद्योगिक मूलभूत ढांचे को निर्मित करने में न केवल संसाधनों को उपलब्ध कराया बल्कि सुनिश्चित आर्थिक नीतियों के साथ प्रभावशाली विकास को जारी रखा। सरकार ने वित्तीय व्यवस्था को रूपांतरित कर दिया तथा इसके पास जापान के सकल राष्ट्रीय उत्पादन को औसतन 14 प्रतिशत था। धन के इस स्रोत की बदौलत यह अपने क्रिकास के कार्यों को लगातार करता रहा। सरकार की कर लगाने की नीति खपत को सीमित करने तथा बचत को प्रोत्साहित करने की थी।

सरकार के खर्च का एक बड़ा भाग सैनिक तंत्र के निर्माण पर खर्च होता था। 1880 के दशक में ये खर्च 18 प्रतिशत के आस-पास था। 1890-1900 तक ये खर्च 34 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा 1901 से 1910 तक सैनिक खर्च में 41 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो गई। इसने आधुनिक क्षेत्र के विकास को लाभान्वित किया। दूसरी नीतियों के कारण आमदनी की असमानतायें पैदा हुईं जिससे धनी वर्गों के बीच बचत को प्रोत्साहन मिला और इसी कारणवश विकास को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

जापानी सरकार ने हस्तक्षेप करने वाली नीति का अनुसरण किया। ऐसा करना सरकार की न केवल राजनीतिक इच्छा थी बल्कि इसको जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधन भी सरकार के पास थे। मेजी नीति ऋण तथा लाभांश की विशेष गारन्टियों के माध्यम से कुछ निश्चित क्षेत्रों के समर्थन के द्वारा निवेश की दिशा को प्रभावित करती थी। आर्थिक गतिविधियों के नैतिक आचार विचार भी समान रूप से महत्वपूर्ण थे। जापान में लाभ स्वयं में एक लक्ष्य नहीं हो सकता था। कन्फ्यूशियस विचारों के प्रभाव के कारण व्यावसायिक लोग राज्य की सेवा करना अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य समझते थे। इसके कारण सरकार व्यावसायिक लोगों के साथ घनिष्ठ तौर पर सामान्य स्वीकृत लक्ष्यों के लिये कार्य करने में सफल हो सकी।

राज्य का उद्योग के क्षेत्र में हस्तक्षेप जिस समय प्रत्यक्ष प्राबंधक के माध्यम से हुआ तब यह सफल न हो सका लेकिन व्यापारिक घरानों (जैबाल्सू) के माध्यम से यह हस्तक्षेप विकास के लिए उत्तर्दायी था। ऐसे परम्परागत क्षेत्रों जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये निर्णायक नहीं थे सरकार उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करती थी। सरकार ने सामाजिक तनावों को रोकने के लिये और सामाजिक सौहार्द की बनाये रखने के लिये कार्य किया। इस प्रकार सरकार ने कृषि में सहकारी समितियों एवं ऋण उपलब्धता कराने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने निरीक्षण सुविधाओं तथा शोध केन्द्रों की स्थापना करके उत्पादन तथा गुणवत्ता को सुधारने का कार्य भी किया। सिदनेय क्राकौर का मत है कि सरकार की नीति सदैव सफल नहीं होती थी और कुल मिलाकर इसने समस्याओं को ही पैदा किया। लेकिन व्यापारियों एवं सरकार के बीच सहयोग के माध्यम से एक अधिक विकासात्मक क्षमता अर्थव्यवस्था से ली जा सकी। यदि यह सहयोग न होता तो संभवतः यह विकासात्मक क्षमता न प्राप्त होती।

बोध प्रश्न 2

- 1) निम्निलिखित में कौन-सा कथन गलत (\times) है और सही ($\sqrt{}$) है। सही ($\sqrt{}$) या गलत (\times) के चिन्ह लगायें।
 - i) जापान के प्रथम मजदूर संघ का निर्माण टोकियो में किया गया।
 - ii) समाजवादी दल को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया गया।
 - iii) अपने भू-स्वामित्व को सुदृढ़ करने के लिये सरकार ने जमींदारों को प्रोत्साहित किया।
 - iv) सरकार किसी भी तरह के शाकाय (सोसाइटी) का विरोध करती थी और उसने इन्सेक्ट सोसाइटी पर प्रतिबंध लगा दिया।

जापान :	आधुनिकीकर ण	की
ओर संब		

2)	जापान के मजदूर	आंदोलन व	हे विकास एवं दमन की 10 पंक्तिय	ों में विवेचना कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	त्तयों में कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक 	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	तयों में कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक 	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	तयों में कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक 	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	तयों में कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक 	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	तयों में कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक 	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	तयों में कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक 	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	तयों में कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक 	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	तयों में कीजिए।
3)	मेजी सरकार की	औद्योगिक 	नीति का मूल्यांकन लगभग 10 पंवि	तयों में कीजिए।

12.8 सारांश-

इस इकाई में हमने मेजी अर्थव्यवस्था के विकास की मुख्य विशेषताओं को पढ़ा। मेजी शासकों ने एक जिटल अर्थव्यवस्था एवं नौकरशाही के ढांचे को तोकुगाबा बकुफु शासकों से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। लेकिन मेजी शासकों ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को संचालित किया तथा उस पर नियंत्रण कायम किया। मेजी शासकों को उत्तराधिकार में ऐसी विशाल वित्तीय समस्याएं मिली जिन्होंने बकुफु की राजनीतिक शक्ति को तोड़ दिया था। अंत में, सैमुराई शासक वर्ग का भूमि पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहा और उनमें से बहुत से नौकरशाही का हिस्सा वन गये। इसका यह तात्पर्य था कि उनके हित किसी विशेष प्रकार की भू-स्वामित्व व्यवस्था के साथ नहीं वंधे थे और इसलिये उन्होनें मेजी सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये परिवर्तनों का कम विरोध किया तथा उनके अनुरूप अपने को ढालने में सफल हुए।

मेजी सरकार ने अपने नव निर्मित संसाधनों को परिवहन, संचार, ऊर्जा क्षेत्रों के निर्माण तथा एक मजवूत सैनिक तंत्र को बनाने में लगा दिया। इन नीतियों ने उनकी इस समझ को प्रतिविवित किया कि यदि जापान राष्ट्र को बने रहना है तव उसको फूकोकू क्योहेई (धनी, देश, मजवूत सेना) के लक्ष्य की नीति का अनुसरण करना ही होगा। मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ नये-नये उद्योगों का आयात किया गया और इनको व्यापारियों को कम कीमतों पर वेचा जाता। इसी के साथ-साथ गहन आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया गया। इन नीतियों ने चुनिन्दा तौर पर निवेश की गारंटी दी, छूटे प्रदान की और संसाधनों को स्वदेशी उद्योग को विकसित करने की और मोड़ दिया।

आर्थिक नीतियां सरकार तथा व्यापरिक नेताओं के बीच समान समझदारी पर आधारित थी और उस केन्द्रीकरण का भाग एवं अंश थीं जो राजनीतिक क्षेत्र में स्थान ग्रहण कर चुका था। आर्थिक क्षेत्र में मुख्य व्यापारिक घरानों को प्रोत्साहित किया गया। इसके कारण दोहरे क्षेत्र की रचना हुई अर्थात् आधुनिक क्षेत्र एवं परम्परागत क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों में आकार, उत्पादकता तथा वेतन में अंतर था। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि परम्परागत क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के विकास एवं वृद्धि में विशेष योगदान किया।

विदेशी ऋणों को कम से कम रखा गया क्योंकि मेजी शासकों को यह चिंता थी कि कहीं वे अपनी संप्रभुता को न खो दें। उन्होंने इन ऋणों का उपयोग कुछ ही अवसरों के लिये किया लेकिन विकास की दर को निर्यातों के द्वारा वित्त प्रदान कर तथा आंतरिक खपत को कम स्तरों पर रख कर बनाये रखा गया। यह केवल मेजी सरकार के उस राजनीतिक नियंत्रण के द्वारा ही संभव हो पाया जिसका उन्होंने उपयोग किया। अल्पतंत्र उस दमनात्मक व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो सका जिसने निर्दयता के साथ विरोध का दमन किया। लेकिन दूसरी तरफ इसने ऐसी नीतियों को जारी रखा जिसने सरकार एवं जनता के बीच वफादारी के संबंधों को स्थापित किया। सम्राट के प्रति वफादारी के इन विचारों के माध्यम से जनता का राज्य के साथ वैचारिक सम्पर्क जापान के आर्थिक विकास में निर्णायक कारक था क्योंकि इसने राष्ट्र के लिये आत्म बलिदान को प्रोत्साहित किया।

विकास की नीतियों ने उस जनता से वस्ली की जिसको बिलदान के भार को सहना पड़ा और इसी के साथ-साथ जापान के पड़ोसी देशों को भी उसकी विस्तारवादी नीतियों के परिणामों का सामना करना पड़ा। इन प्रश्नों पर आगामी इकाईयों में विचार किया गया है। यहां पर यह स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि जापान द्वारा अपनाया गया सैन्यवाद एवं विस्तारवाद सफल आर्थिक विकास से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें राज्य की भूमिका भी निर्णायक थी।

मेजी सरकार ने जापानी अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतिद्वंद्विता से संरक्षण प्रदान किया और उसको सिक्रय सहायता प्रदान कर स्वदेशी उद्योग को विकसित किया। इसके कारण सरकार एवं व्यापार के बीच मजबूत संबंधों की रचना हुई और इसिल्ये उन नीतियों को जो राज्य के राजनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप थीं, कार्यान्वित किया जा सका। जनता एवं पर्यावरण को इस आर्थिक विकास के लिये भारी मूल्य चुकाना पड़ा और राजनीतिक नियंत्रण के कारण उनको इसे वहन करना पड़ा।

12.9 शब्दावली

आधुनिक क्षेत्र: उन आर्थिक गतिविधियों को इस क्षेत्र में रखा गया है जिनके विकास के लिये आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपोग किया गया।

परंपरागत क्षेत्र : इस क्षेत्र के अंतर्गत वे आर्थिक गतिविधियां थीं जो परम्परगात थीं और जिनमें उत्पादन के साधन परंपरागत थे।

जैबात्युः ऐसे एकाधिकार घराने जिनका विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कारोबार पर नियंत्रण था। मुख्य-मुख्य घराने मित्सूई, मित्सूबिशी, सुमितो तथा वासूदा थे। इस शब्द का साहित्यिक अर्थ वित्तीय तंत्र है।

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

- 1) भाग 12.2 में उल्लेखित कृषि सुधारों को आप अपने उत्तर में शामिल करें।
- 2) लौह उद्योग, जहाज निर्माण, रेलवे, विद्युत उत्पादन आदि को सहयोग प्रदान करने में सरकार की नीति की विवेचना करते हुए आप अपने उत्तर का आधार भाग 12.3 एवं 12.4 को बनाये।
- 3) भाग 12.4 देखें।

बोध प्रश्न 2

- 1) i) \times ii) \times iii) $\sqrt{}$ iv) $\sqrt{}$
- 2) आप अपने उत्तर में मजदूर संघों के उद्भव, मजदूर आंदोलन के नेताओं के विचारों, सरकार के द्वारा इस आंदोलन के दमन के प्रयास, प्रतिबंधात्मक कानून आदि को शामिल करें। देखें भाग 12.5।
- 3) देखें भाग 12.7।